सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

–चाणक्य

RNI No. RAJHIN/2001/05699

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

www.hellosarkar.com www.hellosarkar.com www.hellosarkar.com www.hellosarkar.com www.hellosarkar.com

हैलो सरकार

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें

फोन: 0141-2202717
मो: 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-25 | अंक-263 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, बुधवार 27 मई, 2026 | पृष्ठ-4 | मूल्य: 2.50

पंचायत-निकाय चुनाव अवमानना मामला

राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट से मांगी बिना शर्त माफी

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। पंचायत और निकाय चुनाव में देरी को लेकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका मामले में राज्य चुनाव आयोग ने आज हाईकोर्ट में जवाब पेश करते हुए बिना शर्त माफी मांग ली। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने आज इस याचिका पर सुनवाई की।

आयोग की ओर से पेश किए गए जवाब में बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा गया है कि उनका कभी भी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का इरादा नहीं रहा। वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट से कहा कि पंचायत व निकाय चुनाव मामले में हाइकोर्ट की खंडपीठ पहले ही 31 जुलाई तक चुनाव करवाने का फैसला सुना चुकी है इसलिए अब यह याचिका निष्प्रभावी हो गई है। हाईकोर्ट ने इस स्वीकर कर लिया।

आयोग की ओर से हाईकोर्ट में दायर जवाब में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी कानून का पालन करने वाला जिम्मेदार अधिकारी है और उसे अदालत तथा कानून की सर्वोच्चता पर पूरा सम्मान है। जवाब में यह भी कहा गया कि अधिकारी ने कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और न ही जानबूझकर उठाएगा, जिससे हाईकोर्ट या किसी अन्य अदालत के आदेशों का उल्लंघन हो।

जवाब में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अधिकारी से ऐसा कोई कार्य हुआ है, जो अदालत के निर्देशों के अनुरूप नहीं था, तो उसे क्षमा किया जाए। साथ ही अधिकारी ने दोहराया कि उनकी ओर से किसी प्रकार की जानबूझकर अवमानना नहीं की गई है।

गौरतलब है कि मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किए थे। अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा था कि हाईकोर्ट द्वारा तय समय सीमा के बावजूद निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम देरी से क्यों जारी किया गया।

इस बीच पिछले शुक्रवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग की ओर से चुनाव टालने की मांग खारिज कर दी थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक हर हाल में पूरे कराने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने साफ कहा था कि संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव अनिश्चितकाल तक टाले नहीं जा सकते।

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में BSF ने निभाई अहम भूमिका–अमित शाह

हैलो सरकार न्यूज, बीकानेर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को बीकानेर की उस ऐतिहासिक मिट्टी पर पहुंचे, जिसने 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी। सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट (BOP) पर बने वॉच टावर पर चढ़कर गृह मंत्री ने दूरबीन की मदद से सीमा पार के सुरक्षा हालातों का खुद जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीकानेर के सांसद व केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल भी मौजूद रहे। अमित शाह का यह दौरा न केवल रणनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इस बार गृह मंत्री के काफिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सादगी और न्यूनतम प्रोटोकॉल के संदेश की साफ झलक देखने को मिली। नाल एयरफोर्स स्टेशन से लेकर बीएसएफ मुख्यालय तक कोई बड़ा वीवीआईपी तामझाम नजर नहीं आया। सांचू पोस्ट पर पहुंचे गृह मंत्री ने देश की रक्षा में दिन-रात मुस्तैद जवानों का हाथ मिलाकर और उनके कंधे थपथपाकर हौसला बढ़ाया।

नया और आधुनिक सुरक्षा मॉडल रखा सामने

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सांचू पोस्ट पर बीएसएफ (क्चस्स्न) मुख्यालय में अधिकारियों और जवानों को संबोधित करते हुए देश की सुरक्षा को लेकर एक नया और आधुनिक सुरक्षा मॉडल दुनिया के सामने रखा। शाह ने देश की सीमाओं को %स्मार्ट बॉर्डर% में तब्दील करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एक मजबूत चतुष्कोणीय ग्रिड बनाने का आह्वान किया।

अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने दी बदले की धमकी

तेहीरन। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर कहर बरपाया है। हमलों के बाद ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरानी मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नौकाओं को निशाना बनाकर अमेरिकी सेना द्वारा किए गए आत्मरक्षा हमलों के बाद उसे युद्धविराम के किसी भी उल्लंघन का जवाब देने का अधिकार है। यह स्पष्ट नहीं है कि इन हमलों का युद्धविराम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर यह युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ तो पेट्रोल और डीजल को लेकर दुनिया के देशों में हाहाकार मच जाएगी।

92 डॉलर पर पहुंचा कच्चा तेल

28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने ईरान पर संयुक्त हमले शुरू किए। इसके बाद से यह जंग चल रही है। लड़ाई के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था। इसके बाद दुनियाभर में तेल को लेकर संकट छाने लगा। 26 मई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल 94 डॉलर के प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। इससे पहले यह 100 डॉलर को पार कर चुका है। अगर यह लड़ाई जारी रहती है ?तो क्रूड ऑयल के दाम फिर 100 डॉलर के पार जा सकता है। ऐसा हुआ तो पेट्रोल-डीजल और महंगा होने के पूरे आसार है। इससे आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ेगी।

ऑपरेशन म्यूल हंटर में बड़ी कार्रवाई, 83 लाख की साइबर ठगी मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

हैलो सरकार न्यूज, कोटपूतली-बहरोड़ । कोटपूतली-बहरोड़ जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत नीमराना थाना पुलिस ने 83.05 लाख रुपये की ऑनलाइन निवेश ठगी मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप और नकली इन्वेस्टमेंट ऐप के जरिए भारी मुनाफे का लालच देकर पीड़ित से लाखों रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवाए थे।

कोटपूतली-बहरोड़ जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत नीमराना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 83.05 लाख रुपये की ऑनलाइन निवेश ठगी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम और भारी मुनाफे का लालच देकर एक व्यक्ति से लाखों रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए थे।

पुलिस अधीक्षक कोटपूतली-बहरोड़ सतवीर सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमराना सुरेश कुमार खींची तथा पुलिस उपाधीक्षक नीमराना चारुल गुप्ता के सुपरविजन में थाना प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी और बैंकिंग अनुसंधान के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई।

व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फंसाया जाल में

पुलिस के अनुसार, परिवादी को 10 नवंबर 2024 को फ्रक्र10 तद्दश्वद्दह्ल तह्श्वह्लक्ष ह्द्ध ष्टश्वद्धश्वड्ड-ठ्ठद्दह्य ह्ह्वद्दद्दह्ल ष्टद्यह्वड्डफ्र नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। इस ग्रुप में करीब 150 सदस्य मौजूद थे। यहां स्वयं को शेयर मार्केट विशेषज्ञ बताने वाले लोगों ने अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश करवाना शुरू किया। आरोपियों ने प्रोफेसर सीजे जॉर्ज और उसकी कथित असिस्टेंट अनीता रिबेरा के नाम से संपर्क किया और एक लिंक भेजकर "Geo Bloc App" डाउनलोड करवाया।

फर्जी IPO में 400 प्रतिशत मुनाफे का दिया झांसा

इसके बाद प्रतिदिन दोपहर में शेयर खरीदने की टिप्स दी जाती थीं और अगले दिन मुनाफे के साथ बेचने का दावा किया जाता था। कुछ समय बाद फर्जी आईपीओ में 400 प्रतिशत तक लाभ मिलने का झांसा देकर पीड़ित से बड़ी रकम निवेश करवाई गई। निवेश के बाद जब पीड़ित को राशि वापस नहीं मिली, तब उसके साथ हुई ठगी का खुलासा हुआ। मामले में थाना नीमराना पर प्रकरण संख्या 123/25 के तहत धारा 316(2), 318(4), 61(2) बीएनएस तथा 66ष्ट और 66ष्ठ आईटी एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई।

तकनीकी जांच से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

जांच के दौरान पुलिस टीम ने मोबाइल नंबर, बैंक खाते, यूपीआई ट्रांजेक्शन और डिजिटल एविडेंस का गहन विश्लेषण किया। मनी ट्रेल के आधार पर प्रथम लेयर के खाताधारकों की पहचान करते हुए पुलिस ने हरियाणा निवासी योगेश कुमार और भिवाड़ी निवासी दान सिंह गुर्जर उर्फ रवि को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी योगेश कुमार रेवाड़ी का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी दान सिंह गुर्जर उर्फ रवि भिवाड़ी क्षेत्र का निवासी है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने साइबर ठगी की राशि विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर नकदी निकासी करना स्वीकार किया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और मुख्य सरगना की तलाश में जुटी हुई है।

पहले भी हो चुकी है एक गिरफ्तारी

इससे पहले भी इसी मामले में उदयपुर निवासी गौरव नामक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस कार्रवाई में एएसआई जोगेंद्र सिंह, साइबर सेल प्रभारी हेड कांस्टेबल संदीप, कांस्टेबल नागेश, योगेश कुमार और पवन कुमार की विशेष भूमिका रही।

50 लाख में खरीदा गया SI पेपर! परिवार के तीन सदस्य बने आरोपी

हैलो सरकार न्यूज

बांसवाड़ा । राजस्थान की बहुचर्चित एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने राजस्थान राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिपो मैनेजर लोकेंद्र पंडया को डूंगरपुर जिले के वरदा गांव स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को दो दिन के रिमांड पर भेजा गया है। फिलहाल उससे गहन पूछताछ की जा रही है।

एसओजी ने डिपो मैनेजर को दबोचा

50 लाख में खरीदा गया था पेपर

एसओजी जांच में सामने आया है कि लोकेंद्र पंडया के भाई कुंदन कुमार पंडया ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से करीब 50 लाख रुपये में एसआई भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र खरीदा था। आरोप है कि पेपर मिलने के बाद लोकेंद्र पंडया ने अपने बेटे नैतिक, बेटी नेहा और भतीजी रिद्धि को परीक्षा से पहले उन्हीं प्रश्नपत्रों के आधार पर तैयारी करवाई थी।

तीनों अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में हुए थे पास

एसओजी सूत्रों के अनुसार लोकेंद्र पंडया ने तीनों अभ्यर्थियों को विशेष रूप से लिखित परीक्षा की तैयारी करवाई। बाद में वह अपनी गाड़ी से उन्हें जयपुर परीक्षा दिलाने भी लेकर गया था। जांच में सामने आया कि तीनों अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए थे। नैतिक को हिंदी विषय में 200 में से 143.33 और सामान्य ज्ञान में 147.20 अंक मिले थे। वहीं नेहा ने हिंदी में 158.89 और सामान्य ज्ञान में 153.46 अंक प्राप्त किए थे। हालांकि लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद नैतिक, नेहा और रिद्धि फिजिकल टेस्ट में सफल नहीं हो सके। बाद में जांच तेज होने पर जुलाई 2025 में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

दवाइयों के बहाने पहुंचा था संपर्क

जानकारी के अनुसार कुंदन कुमार पंडया सरकारी स्कूल में ग्रेड थर्ड टीचर के पद पर कार्यरत था। सितंबर 2021 में वह बाबूलाल कटारा के संपर्क में आया था। बताया जा रहा है कि कटारा की अस्थमा संबंधी हर्बल दवाइयों के बहाने कुंदन उनके घर पहुंचा था। वहीं कथित रूप से पैसों से भरा लिफाफा सौंपा गया। इसके बाद 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को आयोजित परीक्षा के सभी पेपर उपलब्ध करा दिए गए थे। अब एसओजी पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ते हुए मामले में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

अब तक 142 आरोपी गिरफ्तार

एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में अब तक 142 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह मामला राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के सबसे बड़े मामलों में से एक माना जा रहा है। जांच में सरकारी कर्मचारियों, अभ्यर्थियों और प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत सामने आ चुकी है। राज्य सरकार ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द कर दिया है। अब यह परीक्षा दोबारा 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी।

राजसमंद में 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते पटवारी

खमनोर (राजसमंद)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की इंटेलिजेंस यूनिट उदयपुर ने राजसमंद जिले के खमनोर कस्बे में एक पटवारी को दान की भूमि का नामांतरण खोलने के एवज में 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। घूस लेते पकड़ा गया आरोपी पटवारी राहुल कुमार शर्मा खमनोर तहसील के पटवार हलका सेमा में कार्यरत है, जबकि उसके पास बड़ा भाणुजा पटवार क्षेत्र का भी अतिरिक्त चार्ज है।

गिरफ्तार, नामांतरण खोलने के एवज में मांगी थी घूस

एसीबी की इंटेलिजेंस यूनिट उदयपुर की प्रभारी डॉ. सोनू शेखावत ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसकी दानगृहित भूमि की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण खोलने के बदले आरोपी 7 हजार रुपए रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी राहुल कुमार शर्मा ने परिवादी से एक हजार रुपए रिश्वत की अग्रिम राशि पहले ही ले ली थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई के लिए जाल बिछाया।

आहट हुई तो टॉयलेट में फेंकी रिश्वत की राशि

आरोपी पटवारी ने रिश्वत की राशि लेकर प्रार्थी को खमनोर तहसील मुख्यालय के कस्बे में स्थित अपने सरकारी आवास पर बुलाया, जहां प्रार्थी से उसने 4 हजार रुपए रिश्वत की राशि ले ली। इसी बीच एसीबी की टीम को आते देख आरोपी ने रिश्वत की राशि अपने सरकारी निवास स्थित टॉयलेट के कमोड में फेंक दी, इसे बाद में उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया।

राजस्थान की बेटी नीलम मीणा बनीं पश्चिम बंगाल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गांव में खुशी की लहर

सवाई माधोपुर। जिले के बामनवास उपखंड क्षेत्र के कोयला गांव की बेटी और 1998 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नीलम मीणा को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को पत्र जारी कर उनकी नियुक्ति की जानकारी दी है। इस नियुक्ति के बाद उनके पैतृक गांव कोयला सहित पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार बधाई संदेश साझा कर रहे हैं और क्षेत्र की बेटी को मिली इस बड़ी जिम्मेदारी पर प्रसन्नता जता रहे हैं।

नीलम मीणा को यह जिम्मेदारी ऐसे समय सौंपी गई है, जब पश्चिम बंगाल में चुनावी व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत एवं पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे पहले यह पद मनोज कुमार अग्रवाल के पास था। उनके राज्य के मुख्य सचिव बनने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद रिक्त हो गया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने नीलम मीणा के नाम पर मुहर लगाई।

आखिरी में नीलम मीणा का चयन

जानकारी के अनुसार बंगाल सरकार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद के लिए तीन वरिष्ठ अधिकारियों के नाम चुनाव आयोग को भेजे थे। चुनाव आयोग ने अनुभव और प्रशासनिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए नीलम मीणा का चयन किया।

नीलम मीणा के पास 28 साल का अनुभव

नीलम मीणा पश्चिम बंगाल कैडर की 1998 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 5 फरवरी 1970 को हुआ था। उन्होंने बीएससी और एमए की शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में वे 19 फरवरी 2024 से पश्चिम बंगाल सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें प्रशासनिक सेवा में करीब 28 वर्षों का अनुभव है।

प्रमुख पदों पर दे चुकी हैं सेवाएं

अपने लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। वे प्रमुख सचिव, सचिव, निदेशक, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, संयुक्त सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त निदेशक, उपखंड अधिकारी और सहायक मजिस्ट्रेट जैसे कई अहम पदों पर सेवाएं दे चुकी हैं।

विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका

हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी नीलम मीणा ने चुनावी प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतदान केंद्रों पर निगरानी व्यवस्था, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम से जुड़े कार्यों में उन्होंने अहम जिम्मेदारी निभाई थी। प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि चुनावी प्रबंधन और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए ही उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नहीं रहेगी अतिरिक्त जिम्मेदारी

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर रहते हुए नीलम मीणा कोई अतिरिक्त सरकारी प्रभार नहीं संभालेंगी, ताकि चुनाव संबंधी कार्य पूरी निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ संचालित किए जा सकें।

महंगाई पर कांग्रेस का हल्लाबोल!

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। जयपुर में मंगलवार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में महंगाई के खिलाफ नारे गूंजते रहे।महंगाई के खिलाफ लगे जोरदार नारे

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने पी गई पेट्रोल, खा गई तेल, महंगाई बढ़ाने का बीजेपी का खेल, महंगाई वृद्धि वापस लोफ्र और पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, भारत सरकार ने जनता का जीना तंग कर दिया जैसे नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान हो चुका है और सरकार जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है।

खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर जनता की जेब पर बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग महंगाई से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार जनता की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है।

पानी-बिजली पर त्राहिमाम, सरकार सिर्फ जश्न में डूबी, चिरंजीवी योजना और निकाय चुनाव पर घेरा-गहलोत

हैलो सरकार न्यूज

जोधपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को जोधपुर पहुँचते ही प्रदेश की भाजपा सरकार पर चौतरफा राजनीतिक हमला बोला। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पेयजल किल्लत, स्वास्थ्य सेवाओं में आ रही गिरावट, पंचायत-नगर निगम चुनावों में देरी और अटके हुए विकास कार्यों को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार अपने कार्यकाल का जश्न मनाने में व्यस्त है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता को राहत देने वाले ठोस काम गायब हैं। उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान मंत्री उनके साथ बैठकर अनुभव साझा करते, तो प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संभालना सीख सकते थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने गृह जिले जोधपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में गहराते पानी के संकट को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना (ढ्ढत्ह्रक्क) के जरिए मारवाड़ के कोने-ने तक पानी पहुँचाने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा तैयार किया था। उन्होंने दावा किया कि- नहर के तीसरे चरण के कार्यों के लिए उनकी सरकार ने करीब 1400 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे।

मौजूदा सरकार की कमजोर निगरानी और खराब क्रियान्वयन (इम्पलीमेंटेशन) के कारण आज जनता बूंद-बूंद पानी को तरस रही है।

गहलोत ने अपने कार्यकाल की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना का जिक्र करते हुए कहा कि चिरंजीवी योजना का लाभ अब आम लोगों तक प्रभावी तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी अस्पतालों में मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है और उनसे अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है, जिससे आम आदमी को मजबूरी में अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान जोधपुर में बने मेडिकल कॉलेज, नए अस्पताल भवनों और विश्वविद्यालयों जैसी आधुनिक सुविधाओं को भी वर्तमान सरकार ठीक से संभाल नहीं पा रही है।

लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव- पंचायत और नगर निगम चुनावों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए गहलोत ने कहा कि चुनाव करवाने में लगातार जानबूझकर देरी की जा रही है। इस ढुलमुल रवैए पर अदालत भी सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी कर चुकी है।

पेपर लीक पर सिर्फ प्रचार- भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक के मामलों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपियों और माफियाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई की शुरुआत उनकी सरकार ने की थी, जबकि मौजूदा सरकार केवल प्रचार और क्रेडिट लेने तक ही सीमित दिखाई दे रही है।

गहलोत ने अंत में कहा कि प्रदेश की जनता पानी, बिजली और इलाज जैसी बुनियादी समस्याओं से त्रस्त है, इसलिए सरकार को उत्सवों से बाहर निकलकर जमीनी मुद्दों पर गंभीरता दिखानी चाहिए।

यशस्वी प्रधानमंत्री के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के बेमिसाल 12 साल

(लेखक- सुरेश पचौरी)

नरेन्द्र मोदी ऐसे कर्मयोगी हैं, जो सर्व भवन्तु सुखिन- के राष्ट्र-भाव को चरितार्थ करते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वादस का संकल्प लेकर भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने में अहर्निश लगे हुए हैं। संक्षेप में कहा जाए तो मोदी जी के नेतृत्वर वाली केन्द्रम सरकार का सिद्धांत है- रिफार्म, परफार्म एवं ट्रांसफॉर्म। प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि के लिए अपनी प्राथमिकता में GYAN को रखा है। G का तात्पर्य गरीब, Y का तात्पर्य युवा, A का तात्पर्य अन्नदाता किसान और N का तात्पर्य नारी।

लोकतीत्र में श्रेष्ठ् नेतृत्वा की पहचान नीति, नीयत और निष्ठाल की कसौटी पर खरा उतरने से होती है। यह एक सुखद पक्ष है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस मापदंड पर सर्वथा खरे उतरे हैं। देश की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें देश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की प्रथम बार शपथ ली। बतौर प्रधानमंत्री अपने 12 वर्ष के लगातार कार्यकाल में उन्होंने राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में स्वीकारा तथा देशवासियों का विश्वास जीतने में कामयाब रहे।

नरेन्द्र मोदी ऐसे कर्मयोगी हैं, जो सर्व भवन्तुं सुखिन- के राष्ट्र-भाव को चरितार्थ करते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वादस का संकल्प लेकर भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने में अहर्निश लगे हुए हैं। संक्षेप में कहा जाए तो मोदी जी के नेतृत्वर वाली केन्द्रम सरकार का सिद्धांत है- रिफार्म, परफार्म एवं ट्रांसफॉर्म। प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि के लिए अपनी प्राथमिकता में GYAN को रखा है। G का तात्पर्य गरीब, Y का तात्पर्य युवा, A का तात्पर्य अन्नदाता किसान और N का तात्पर्य नारी। वर्तमान में केंद्र सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं में इन पर अधिक फोकस किया है।

गरीब कल्याणि कार्यक्रम

केन्द्रा सरकार ने समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित एवं सर्वहारा वर्ग के हितों को दृष्टिगत रखते हुए अनेक ऐतिहासिक एवं कल्याणकारी निर्णय लिये हैं। श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वकच्छद भारत अभियान की शुरुआत की। पिछले 12 वर्षों में यह अभियान एक जन आंदोलन बन गया है। साथ ही उज्जएवला योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत करोड़ो लोग लाभान्वित हुये हैं।

युवा शक्ति की बेहतरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकताओं में युवाओं के लिए अच्छाल स्वामस्थ्ह , फिटनेस और उन्हें उचित हुनर से लैस करना शामिल है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा कोष योजना और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने भारत को विकसित राष्ट्री की ओर आगे बढ़ाया है।

किसान कल्याण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन बहुत साफ है कि किसानों को उनकी पैदावार का सही दाम मिले। इस बाबत् फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में रिकार्ड बढ़ोत्तरी की। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को उनके बैंक खातों में हर चार महीनों में दो हजार रुपये पहुंचाये जाते हैं। पीएम फसल बीमा योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएमआरकेवाई) से अन्ननदाता लाभान्वित हो रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण मोदी सरकार के विकास एजेंडे का प्रमुख हिस्सा है। मातृवंदन योजना, नारी शक्ति वंदन और 33 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद जगी है। केन्द्रा सरकार का लक्ष्यस तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का है, जिनमें से लगभग 1 करोड़ 10 लाख लखपति दीदी अपना गरिमामय जीवन जी रही हैं। बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों का आत्मषसम्माकन बढ़ा है। तीन तलाक कानून की समाप्ति से मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

स्वाषस्थ्कर सुविधाओं में वृद्धि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्वर वाली केन्द्रा सरकार ने देश में लगभग 2 लाख आयुष्मामन आरोग्य मंदिर खोले हैं। मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि समाज के हर वर्ग खासकर सामान्य लोगों तक सतीन , सुलभ एवं गुणवत्ता पूर्ण स्वायस्थ्ति सेवाएं पहुंचें। इस दिशा में जारी प्रयास के परिणाम स्वरूप अस्पसताल,इलाज और दवाओं पर होने वाला खर्च निरन्तईर कम होता जा रहा है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी वैक्सीलन के आविष्कार में प्रेरक भूमिका निभाई।

सांस्कृ्तिक विरासत का संरक्षण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना संकल्प् विरासत का, संरक्षण भी और विकास भी के परिणाम स्वगरूप अयोध्यात में रामलला की दिव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठो सम्पपन्नअ हुई। काशी में बाबा विश्वानाथ कॉरिडोर, उज्जैरन में महाकाल लोक, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, बद्रीनाथ क्षेत्र का विकास, करतार साहब कॉरिडोर को खुलवाना, हेमकुण्डय साहब और गिरनार में रोपवे बनाना, नमामि गंगे योजना, तिरुवल्लु में कल्चसरल सेन्टसर बनाना आदि उल्लेखनीय कार्यों से भारत आत्मगगौरव के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्वत में स्वमदेशी चिंतन आधुनिक देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चिंतन का आधार बन रहा है।

धारा- 370 की समाप्ति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मूू-कश्मीरर में धारा 370 समाप्त कर दी। धारा-370 को हटाना एक इतिहास की धारा को मोड़ने वाला निर्णय साबित हुआ है, इससे जम्मूक-कश्मीरर में खुशहाली की राह खुली है और देश की एकता व अखण्डतता का ताना-बाना मजबूत हुआ है।

आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति

प्रधानमंत्री श्री मोदी की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति बहुत स्पष्ट है। पाकिस्ता न के हुक्म7रानों, पाकिस्ता नी सेना, आईएसआई और उनके द्वारा पोषित आतंकवादी संगठनों ने भारत में समय-समय पर आतंकवादी हमले किये हैं, जिसमें निर्दोष भारतीयों की जानें गई हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारतीय सेना को पाकिस्तारन पर जवाबी कार्रवाई के लिए खुली छूट दी। भारतीय सेना ने आपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तासन के आतंकवादी अड्डों एवं प्रशिक्षण शिविरों को जमींदोज कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने विश्वय समुदाय के सामने भारत का पक्ष रखने के निए सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डाल भेजने का फैसला लिया, जो प्रभावी कदम साबित हुआ। यशस्वीन प्रधानमंत्री के नेतृत्वष में केन्द्रत सरकार की सर्वोच्चष प्राथमिकता अपने नागरिकों का कल्यानण सुनिक्षतत करना है। घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण के लिये केन्द्री सरकार ने बहुआयामी रणनीति बनाई है।

भारतीय सेना को सम्मान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न युद्धों के दौरान शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों की पुण्य स्मृति में दिल्ली में राष्ट्रीय शौर्य स्मारक एवं नेशनल वॉर मेमोरियल निर्मित कराये गये। पूर्व सैनिकों के लिए 'वन रैंक वन पेंशन' योजना लागू की गई। केंद्र सरकार ने देश के रक्षा बजट में काफी बढ़ोत्तरी की। भारत आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन जैसे तेजस लड़ाकू विमान, ब्रम्होस मिसाइल और अग्नि मिसाइल सिस्टम ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया है। आज भारत लगभग 100 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। जब देश एकजुट होता है और नेशन फर्स्टर की भावना से काम करता है, तो ऐसे मजबूत निर्णय और परिणाम सामने आते हैं।

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्ता न के भीतर 100 किमी तक घुसकर कार्यावाही की। यह भारत की सैनय क्षमता, राजनीतिक इच्छ्रशक्ति और राष्ट्री य संकल्पर का प्रतीक है। भारत की मजबूत सैन्यक शक्ति, भारत के मिसाइलों और ड्रोन ने पाकिस्ता न एयरबेस को भारी नुकसान पहुँचाया। भारत ने रॉफेल, सुखोई, ब्रम्हौस, एस-400, एस-125, स्कंल्प, मिसाइल, हेमर मिसाइल बम का जहॉं एक ओंर इस्तोमाल किया। वहीं स्वोदेशी निर्मित आकाश मिसाइल, समर, नागास्त्र0 का इस्ते माल करके पाकिस्ताइन के अनेक ड्रोन्सि व मिसाइल नष्टप कर दिये। डीआरडीओ के अभद्य रक्षा कवच ने पाकिस्तारन के एयर डिफेंस सिस्ट्म को तबाह कर दिया। इससे भारत के एयर डिफेंस सिस्ट्म के सक्षम होने की और भारत निर्मित हथियारों ओर मिसाइलों की श्रेष्ठपता साबित हो गई।

नया भारत विकसित भारत हो इसके लिये आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। नागरिकता संशोधन कानून, ई-गवर्नेन्स, डिजिटल इंफास्ट्रक्चर का विस्तार, अक्षय ऊर्जा में वृद्धि, पीएम गतिशक्ति आदि योजनाएं देश को विकसित एवं खुशहाल भारत की ओर ले जाने की दूरगामी पहल है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जीवन राष्ट्रयज्ञ की समिधा है, और उनकी कामना रन्तिदेव की तरह राष्ट्र को वैभव पूर्ण बनाने की है।

रन्तिदेव ने कहा था -

''न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवम्।
कामये दु:खतप्तानां, प्राणिनामार्त नाशनम्।।''

अर्थात् - न मुझे राज्य की कामना है, न स्वर्ग की और न पुनर्जन्म से छुटकारा पाने की। मेरी कामना तो यह है कि मैं दुखों से संतप्त प्राणियों के काम आ सकूं। इसी भावना से स्वप्नदृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भारत को दुनिया के समृद्ध और शक्तिशाली देशों में शुमार करने की दिशा में सन्नद्ध व संकल्पबद्ध हैं।

(लेखक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठस नेता एवं भारत सरकार में रक्षा उत्पादन, कार्मिक व संसदीय कार्य राज्यमंत्री रहे हैं)

संपादकीय

एक और मिल्खा सिंह

एक प्रेरक कहावत है कि सुबह जिसकी हुई, सचमुच वो सारी रात नहीं सोया होगा। आज जब हम पंजाब के पुत्र गुरिंदरवीर सिंह की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी की बात कर रहे हैं तो हमें इस मुकाम तक पहुंचने के उसके संघर्ष को भी याद करना चाहिए। कोई भी कामयाबी रातों-रात नहीं मिलती। महज 10.09 सेकंड में सौ मीटर की रेस पूरी करने वाले गुरिंदरवीर सिंह ने, निस्संदेह नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर देशवासियों को गर्व करने का मौका दिया है। निर्विवाद रूप से उनके भारत के सबसे तेज धावक बनने की कहानी महज चंद घड़ियों की बदौलत नहीं नापी जा सकती। गांव की धूल से भरी सड़कों में उनका अभ्यास, प्रशिक्षण मैदानों में पसीने के साथ थका देने वाला सफर और संसाधन के अभावों से जूझकर ही वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वहीं इस कामयाबी में उनके परिवार का खामोश त्याग भी शामिल है, जो उनकी कामयाबी के बाद ही सुर्खियों में नजर आ पाया है। जालंधर के निकट स्थित पटियाल गांव के स्प्रिंट किंग गुरिंदरवीर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप में जब सौ मीटर की दौड़ 10.09 सेकेंड में पूरी की तो इस मुकाम तक पहुंचने वाले वे पहले भारतीय थे। एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। इस इतिहास को रचकर गुरिंदरवीर सिंह देश के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में शामिल हो गए हैं। इस सफलता का एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि इस कामयाबी के बाद वे स्वत- ही राष्ट्रमंडल खेलों में खेलने के हकदार हो गए हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में एक और पदक जीतने की उम्मीद फिर से जगा दी है। उल्लेखनीय है कि स्प्रिंट किंग गुरिंदरवीर का सौ मीटर की दौड़ पूरी करने का यह समय इस सीजन में एशिया का दूसरा सबसे तेज समय है। वे जापान के फुकुतो कोमुरो से महज .01 सेकेंड ही पीछे रहे हैं। विश्वास करना चाहिए कि भविष्य में गुरिंदरवीर सिंह नये मुकाम हासिल करेंगे। यह विरोधाभास ही है कि जब कोई खिलाड़ी रिकॉर्ड कामयाबी हासिल करता है तो हम उसे पलक-पावड़ों पर बैठा देते हैं। मान-सम्मान और पुरस्कार देते हैं। लेकिन यदि छोटी उम्र में ही प्रतिभा को पहचान करके उसे पर्याप्त संसाधन व प्रशिक्षण प्रदान करें तो देश में कई गुरिंदरवीर तैयार हो सकते हैं। गुरिंदरवीर सिंह की इस कामयाबी के पीछे कई प्रेरणादायक कहानियां भी निहित हैं। उनका मानवीय पहलू हमारे समाज की सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। उनके पिता ने अपने बेटे को दौड़ के अभ्यास हेतु भेजने के लिये किश्तों में एक पुराना स्कूटर खरीदा था। जो बताता है कि एक तरफ क्रिकेट खिलाड़ियों पर लाखों-करोड़ों वारे जाते हैं तो दूसरी ओर परंपरागत खेलों से जुड़े खिलाड़ियों का संघर्ष कितना बड़ा है। वहीं गुरिंदरवीर सिंह को तराशने-निखारने की यात्रा में भारतीय नौसेना के योगदान को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जिसने गुरिंदरवीर सिंह को ट्रैक पर उत्कृष्ट सफलता हासिल करने हेतु संबल दिया। निस्संदेह, गांव-कस्बों से निकलने वाली प्रतिभाओं की कामयाबी के पीछे सीमित संसाधनों वाले माता-पिता के दृढ़ संकल्प और त्याग की कहानी छिपी रहती है। गुरिंदरवीर सिंह जैसे राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी के पीछे एक परिवार शिद्दत के साथ खड़ा होता है, जो उसके सुनहरे भविष्य के लिये अपनी सुख-सुविधा, बचत व आर्थिक सुरक्षा तक त्याग कर देता है। गुरिंदरवीर सिंह के दिल में गांव और साधारण परिवारों में पले-बढ़े बच्चों के संघर्ष के प्रति खासा सम्मान है। वे उन हजारों नवोदित खिलाड़ियों के लिये प्रेरणापुंज हैं जो अपनी पृष्ठभूमि वाले एक खिलाड़ी को राष्ट्रीय फलक पर चमकता देख रहे हैं।

जेन जी को गुमराह करना अब सरकार के लिए आसान नहीं

(लेखक- दिलीप कुमार पाठक)

इस गंभीर संकट से निकलने के लिए सरकारों को अब बिना देरी किए कुछ पक्के कदम उठाने होंगे। सबसे पहले पेपर लीक के खिलाफ बने कानून को पूरी ईमानदारी से जमीन पर उतारना होगा। इसके साथ ही यूपीएससी की तर्ज पर सभी राज्यों को एक तय परीक्षा कैलेंडर जारी करना चाहिए। खाली पड़े लाखों सरकारी पदों को तुरंत बिना किसी धांधली के भरा जाना जरूरी है।

भारत आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां हमारे जेन जी का सब्र अब पूरी तरह टूट रहा है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा तूफान आया जिसने बड़े-बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी। इंटरनेट पर खड़े हुए एक डिजिटल आंदोलन ने सिर्फ चार-पांच दिनों के भीतर इंस्टाग्राम पर दो करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स जोड़ लिए। इस मोर्चे ने देश की दिग्गज राजनीतिक पार्टियों को भी सोशल मीडिया की दौड़ में पीछे छोड़ दिया। यह कोई हंसी-मजाक या मीम नही है, बल्कि देश के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं का गुस्सा है, जिसे सरकार अब हल्के में नहीं ले सकती।

जेन जी के इस जुड़ाव का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि आंदोलन की वेबसाइट पर कुछ ही दिनों में दस लाख से ज्यादा लोगों ने अपना नाम लिखवा दिया और पेपर लीक के खिलाफ छह लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन दस्तखत कर दिए। इस पूरे बवाल की चिंगारी सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान भड़की। अदालत में एक केस के दौरान चीफ जस्टिस ने टिप्पणी कर दी कि कुछ बेरोजगार युवा सिस्टम, मीडिया, कानून और आरटीआई के भीतर कॉकरोच की तरह घुस जाते हैं और हर किसी पर हमला करने लगते हैं। जब देश भर के जेन जी में इस बात को लेकर गुस्सा फैला तो चीफ जस्टिस को सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया और उनका इशारा सभी बेरोजगारों की तरफ नहीं, बल्कि नकली डिग्री वालों और सिस्टम का फायदा उठाने वालों की तरफ था। लेकिन जेन जी इस सफाई से शांत नहीं हुए। उन्होंने इस अपमान को अपनी लाचारी और बेरोजगारी से जोड़कर देखा और सोशल मीडिया पर एक तगड़ा डिजिटल मोर्चा खोल दिया। यह गुस्सा सिर्फ एक बयान से नहीं भड़का है, बल्कि इसके पीछे सालों से जमा हो रही हताशा है।

भारत हर साल करीब अस्सी लाख से ज्यादा ग्रेजुएट्स तैयार करता है वहीं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट कहती है कि देश के कुल बेरोजगारों में तिरासी प्रतिशत हिस्सेदारी अकेले जेन जी की है। सबसे डरावनी बात यह है कि ऊंचे पढ़े-लिखे लोगों में बेरोजगारी दर उनतीस प्रतिशत के आसपास है। इसका सीधा मतलब यह है कि डिग्री जितनी बड़ी है, नौकरी की गारंटी उतनी ही कम है। बेरोजगारी का यह तनाव युवाओं को मानसिक रूप से इस कदर तोड़ रहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक, कुल खुदकुशी के मामलों में बेरोजगारों की हिस्सेदारी जो साल पंचांगबे में सिर्फ एक दशमलव आठ प्रतिशत थी, वह अब बढ़कर नौ दशमलव दो प्रतिशत से ऊपर जा चुकी है। यह चार सौ ग्यारह प्रतिशत की भयानक बढ़ोतरी है। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में पिछले कुछ सालों में दर्जनों बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं या उन्हें रद्द किया गया है। यूपी पुलिस भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती और राजस्थान में रीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के बार-बार लीक होने से करोड़ों लोगों का भविष्य अधर में लटक गया है। सालों तक कमरों में बंद रहकर तैयारी करने वाले युवाओं का पैसा, समय और मानसिक संतुलन इस भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट चढ़ जाता है। ऊपर से महंगाई की मार ऐसी है कि खाने-पीने से लेकर पढ़ाई और रहने का खर्च लगातार बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर बनने की उम्र में देश का पढ़ा-लिखा तबका अपने मां-बाप के पैसों पर जीने को मजबूर है।

देश की पैंसठ प्रतिशत आबादी पैंतीस साल से कम उम्र की है। आज का जेन जी चुपचाप अपमान सहकर घर बैठने वाली पीढ़ी नहीं है। वे तकनीक को बेहतर समझते हैं, जब सरकार ने इस बढ़ते डिजिटल प्रभाव को देखकर उनका मुख्य सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करवाया तो जेन जी ने तुरंत दूसरा मोर्चा खड़ा कर दिया। यह जिद्द और तेवर साफ बताते हैं कि अब उनकी आवाज को दबाना नामुमकिन है। इस पीढ़ी ने व्यवस्था को आईना दिखा दिया है कि तुम भले ही हमें हाशिए पर धकेल दो, हम लड़ना जानते हैं। सरकार को अब यह गहराई से समझना होगा कि करोड़ों लोगों का यह डिजिटल जुड़ाव हवा का रुख मोड़ सकता है। इस गंभीर संकट से निकलने के लिए सरकारों को अब बिना देरी किए कुछ पक्के कदम उठाने होंगे। सबसे पहले पेपर लीक के खिलाफ बने कानून को पूरी ईमानदारी से जमीन पर उतारना होगा। इसके साथ ही यूपीएससी की तर्ज पर सभी राज्यों को एक तय परीक्षा कैलेंडर जारी करना चाहिए। खाली पड़े लाखों सरकारी पदों को तुरंत बिना किसी धांधली के भरा जाना जरूरी है। अगर पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी पर अब भी ऐसी ठोस नीतियां नहीं बनाई गईं और जेन जी की दिक्कतों को सिर्फ इंटरनेट का एक अस्थाई ट्रेंड समझकर छोड़ दिया गया, तो आने वाले समय में यह शांत आक्रोश सड़कों पर उतरेगा। यह स्थिति किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बनेगी क्योंकि आज की इस नई पीढ़ी को अब सिर्फ खोखले वादे नहीं बल्कि इज्ज़त और रोजगार चाहिए।

(लेखक पत्रकार हैं)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

धर्म का आदर

स्वामी श्रद्धानंद महर्षि दयानंद के योग्य शिष्य थे। उन्होंने शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए देश के कई हिस्सों में गुरुकुल कांगड़ी और अन्य संस्थाओं की स्थापना की थी। एक बार रुड़की चर्च के पादरी फादर विलियम ने स्वामी जी से पत्र लिखकर कहा- स्वामी जी, मुझे लगता है कि अगर मैं हिंदी सीख लूं तो शायद भारत में मैं अपने धर्म का प्रचार बेहतर ढंग से कर पाऊंगा। क्या इसके लिए आप मुझे अपने गुरुकुल में प्रवेश दे सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि अपने अध्ययन के दौरान मैं ईसाई धर्म की चर्चा नहीं करूंगा और उसके प्रचार की कोई कोशिश नहीं करूंगा।

स्वामी जी ने पत्र के जवाब में लिखा- फादर, गुरुकुल कांगड़ी में आपका खुले दिल से स्वागत है। आप यहां अतिथि बनकर हमारी सेवाएं ले सकते हैं। मगर आपको एक वचन देना होगा। जब तक आप यहां रहेंगे तब तक आप अपने धर्म का खुलकर प्रचार-प्रसार करेंगे ताकि हमारे छात्र भी ईसा मसीह के उपदेशों को समझ सकें और उन्हें ग्रहण कर सकें। मैं चाहता हूं कि हमारे छात्र धर्मों का आदर करना सीखें। धर्म प्रेम सिखाता है बैर नहीं। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने अलावा दूसरे धर्मों को भी जाने। अधिक से अधिक धर्मों के विषय में जानकर हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं।

स्वामी जी का यह जवाब पढ़कर फादर अभिभूत हो गए। वे जब तक गुरुकुल में रहे, छात्रों को ईसाई धर्म के बारे में बताते रहे। यहां रहकर भारतीयों को लेकर उनकी कई धारणाएं बदल गईं। वे जीवन भर गुरुकुल के लिए कार्य करते रहे।

विचार मंथन

भय, भूख, लालच और सपनों की राजनीति

(लेखक-सनत जैन)

स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों की राजनीति पर दृष्टि डालें, तो स्पष्ट दिखाई देता है, भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना धीरे-धीरे सत्ता केंद्रित राजनीति में बदलती चली गई। वर्तमान राजनीति का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण से अधिक सत्ता प्राप्ति और सत्ता को बनाए रखना है। स्वतंत्रता आंदोलन से निकला नेतृत्व त्याग, संघर्ष और वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रतीक था। संविधान निर्माताओं ने भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए जो संविधान तैयार किया था, उसमें अंतिम शक्ति जनता के हाथ में रहे। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का संतुलन स्थापित किया गया। नागरिकों और मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। इसे चौथा स्तंभ भी संविधान का माना गया। ताकि कोई भी संस्था निरंकुश न हो सके। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जिस तरह से प्रकृति का संचालन है, संविधान निर्माताओं ने यही व्यवस्था भारतीय संविधान में की। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती 25 वर्षों में संसाधनों की भारी कमी, युद्ध, अकाल और आर्थिक संकट के बावजूद, तब की सरकारों ने बड़े-बड़े विकास कार्य किये। बड़े-बड़े सार्वजनिक उपक्रम तैयार किया। बड़े-बड़े शिक्षा के संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान उसी अवधि में तैयार किए गए। योजना आयोग के माध्यम से केंद्र एवं राज्यों के बीच संघीय शासन व्यवस्था तथा संसाधनों का बंटवारा करने संवैधानिक संस्था बनाई गई। उस समय शासन व्यवस्था में नैतिकता दिखाई देती थी। सभी संवैधानिक संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेह थीं। 1947, 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान अकाल, खाद्यान्न संकट, तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास टैक्स के रूप में जब सीमित आर्थिक संसाधन थे। भारत ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्रता देते हुए उन्हें मजबूत किया। विकास की आधारशिला रखी। जब कोई व्यवस्था नहीं थी, उस दौर के नेतृत्व में वैचारिक मतभेद होने के बाद भी राष्ट्रहित सर्वोपरि था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 का युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण भारत की राजनीतिक इच्छाशक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वैश्विक स्तर पर आज भी माना जाता है।

1977 के बाद भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया। 1971 के युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर भारत में बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए। जो लंबे समय तक लागू रहे। भारत को ऊर्जा संकट का सामना कई वर्षों तक करना पड़ा। खाद्यान्न संकट का भी सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने इसका मुकाबला किया। प्रतिबंधों के कारण भारत में खाद्यान्न संकट महंगाई और मुनाफाखोरी बढ़, जनता की नाराजी बढ़ी। 1975 में सारे देश में आंदोलन शुरू हो गए। छात्र, ट्रेड यूनियन, विपक्षी राजनीतिक दल सब सड़कों पर आ गए। 1975 में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जयप्रकाश नारायण ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की- सेना और पुलिस सरकार की बात नहीं माने। इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ गई थी। इंदिरा गांधी ने इस स्थिति से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान था। सांसद ने भी इसकी पुष्टि की। आपातकाल के विरोध से पैदा हुई राजनीति सत्ता की राजनीति में वैचारिक स्थिरता नहीं ला सकी। गठबंधन, अवसरवाद और सत्ता की होड़ ने राजनीति की दिशा बदल दी। लगभग ढाई वर्ष के बाद केंद्र में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी वह गिर गई। 1980 में पुन: चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गांधी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई। 1984 में प्रधानमंत्री निवास में गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 75 वर्ष के इतिहास में वह सबसे ज्यादा सीटों के साथ चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने। उन्होंने रक्षा सोदों में दलाली बंद करने का निर्णय लिया। तत्कालीन रक्षा मंत्री वीपी सिंह थे, उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर बोफोर्स खरीदी मे कमीशन लेने और विदेशी बैंक में जमा करने का आरोप लगाया। 1989 के चुनाव में भ्रष्टाचार राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत नही मिला। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। जिस बोफोर्स घोटाले का उन्होंने आरोप लगाया था, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वह उसे प्रमाणित नहीं कर सके। धीरे-धीरे राजनीतिक दलों का लक्ष्य जनसेवा से हटकर चुनावी प्रबंधन और सत्ता के सिंहासन तक सीमित होता चला गया। भारत की राजनीति में नैतिकता का स्थान अनैतिकता में बदलता चला गया। राजनीति स्वार्थ पर आधारित हो गई। 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत को नई दिशा दी। उदारीकरण के बाद भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा। प्रधानमंत्री नरसिंहाराव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक दिशा दी। 2004 मे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। वह 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इन 10 वर्षों में भारत में बड़ी तेजी के साथ विकास हुआ। वह काम करने में विश्वास करते थे। वह राजनीतिज्ञ नहीं थे। इसका खामियाजा कांग्रेस को संगठन स्तर पर भुगतना पड़ा।

केजी-बेसिन गैस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुलह प्रक्रिया पर सहमति जताई

शीर्ष अदालत ने जुलाई के तीसरे सप्ताह तक सुनवाई स्थगित की

नई दिल्ली ।

उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की केंद्र सरकार के साथ कृष्णा-गोदावरी बेसिन गैस विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की नई अर्जी स्वीकार कर ली है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि दोनों पक्ष समाधान निकाल लेते हैं, तो लंबित अपील का निपटारा कर दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के इस उल्लेख का संज्ञान लिया कि सुलह प्रक्रिया के लिए आवेदन किया गया है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने सरकार की ओर से इस अनुरोध पर विचार करने की सहमति जताई। इस पर न्यायालय ने मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह तक स्थगित कर दी। पीठ ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, यदि विवाद सुलह से सुलझता है तो हमें खुशी होगी। गौरतलब है कि 20 मई को इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस और उसकी साझेदार कंपनियों की मध्यस्थता की पिछली मांग को ठुकरा दिया था। यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर अपीलों से संबंधित है, जिसने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के रिलायंस के पक्ष में दिए गए फैसले को रद्द कर दिया था। कंपनियों पर केजी बेसिन के ऐसे गैस भंडारों से गैस निकालने का आरोप है, जिनका दोहन करने का उन्हें अधिकार नहीं था।

ताइवान बना दुनिया का पांचवां बड़ा शेयर बाजार, भारत को पीछे छोड़ा

ताइवान का बाजार मूल्य 4.95 ट्रिलियन डॉलर पहुंचा, जबकि भारत 4.92 ट्रिलियन डॉलर के साथ छठे स्थान पर

नई दिल्ली ।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्रांति की लहर पर सवार होकर ताइवान ने वैश्विक शेयर बाजार में एक बड़ी छलांग लगाई है। देश ने भारत को पीछे छोड़ते हुए सोमवार तक दुनिया के पांचवें सबसे बड़े इक्विटी मार्केट का दर्जा हासिल कर लिया है, जिसका कुल बाजार पूंजीकरण 4.95 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय मुख्य रूप से दिग्गज चिप निर्माता कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग कंपनी को जाता है, जिसकी एआई चिप्स की बढ़ती वैश्विक मांग ने ताइवानी बाजार को अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचाया है। यह न सिर्फ ताइवान की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, बल्कि वैश्विक टेक सप्लाई चेन में उसके केंद्रीय महत्व को भी रेखांकित करता है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को ताइवान के शेयर बाजार का कुल मार्केट कैप 4.95 ट्रिलियन डॉलर दर्ज किया गया, जबकि भारत का बाजार मूल्य घटकर 4.92 ट्रिलियन डॉलर रह गया। इस बदलाव के साथ, दुनिया के सबसे बड़े इक्विटी बाजारों की सूची में अब अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद ताइवान का नाम शामिल हो गया है। ताइवान की इस शानदार प्रगति का सबसे प्रमुख कारण दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट चिप निर्माता टीएसएमसी रही है। कंपनी के शेयरों में इस साल अकेले करीब 49 प्रतिशत की जबरदस्त उछाल देखी गई है। एआई सेक्टर में अभूतपूर्व मांग बढ़ने से टीएसएमसी को सीधा फायदा मिला है, क्योंकि उसके उन्नत सेमीकंडक्टर वैश्विक टेक दिग्गजों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स के निर्माण में रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। एने विडिया जैसी कंपनियों के लिए चिप्स बनाने वाली टीएसएमसी ने एआई चिप्स की बढ़ती जरूरत को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रुपया 17 पैसे गिरकर 95.43 प्रति डॉलर पर खुला

रुपया पिछले दिन 95.26 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था

मुंबई ।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में मंगलवार को रुपया शुरुआती कारोबार में 17 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.43 पर आ गया। महीने के अंत में डॉलर की मांग बढ़ने और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से निवेशकों की धारणा पर दबाव पड़ा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव बने रहने तक रुपये पर व्यापक दबाव जारी रह सकता है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के उपाय और तरलता बढ़ाने से निकट अवधि में कुछ राहत दे सकते हैं और उतार-चढ़ाव को सीमित कर सकते हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 95.43 प्रति डॉलर पर खुला, जो पिछले बंद स्तर से 17 पैसे कमजोर है। सोमवार को रुपया 34 पैसे मजबूत होकर 95.26 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मंगलवार को भारतीय रुपया 45 अंक नीचे आकर 95.71 पर बंद हुआ। इससे पहले आज सुबह अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया शुरुआती कारोबार में 17 पैसे फिसलकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.43 पर आ गया। महीने के अंत में डॉलर की मांग बढ़ने और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से निवेशकों की धारणा पर दबाव पड़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 95.43 प्रति डॉलर पर खुला, जो पिछले बंद स्तर से 17 पैसे कमजोर है। सोमवार को रुपया 34 पैसे मजबूत होकर 95.26 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

कारोबारियों के अनुसार उस दिन आरबीआई की डॉलर बिक्री से रुपये को ऊपरी स्तरों पर

एचपीसीएल की ईंधन बिक्री में मजबूत उछाल

नई दिल्ली ।

सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी तेल विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) ने मई महीने के शुरुआती 24 दिनों में ईंधन बिक्री में शानदार वृद्धि दर्ज की है, जो आर्थिक गतिविधियों में तेजी और बढ़ी हुई उपभोक्ता मांग का स्पष्ट संकेत है। कंपनी के अनुसार 1 से 24 मई के दौरान पेट्रोल की खुदरा बिक्री 7.36 लाख टन दर्ज की गई, जो पिछले साल की इसी अवधि के 7 लाख टन से 5 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह डीजल की खुदरा बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 7 प्रतिशत बढ़कर 14.27 लाख टन पर पहुंच गई। पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने 13.35 लाख टन डीजल बेचे थे। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है और लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, जिससे ईंधन की खपत में इजाफा हुआ है।

महंगा हुआ घर खरीदना, बिक्री मूल्य 16 फीसदी बढ़ा

आपूर्ति बढ़ने से बिना बिके मकानों की संख्या 13 फीसदी बढ़कर 12 लाख इकाई हुई

नई दिल्ली।

भारत के प्रमुख शहरों में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान घरों की बिक्री में एक दिलचस्प प्रवृत्ति देखने को मिली है। एक रिपोर्ट बताती है कि जहां घरों की बिक्री का कुल मूल्य 16 फीसदी बढ़कर 9.33 लाख करोड़ रुपये हो गया, वहीं बेचे गए घरों की संख्या में 1 फीसदी की मामूली गिरावट आई। एक गैर-ब्रोकरेज रियल एस्टेट अनुसंधान और डेटा विश्लेषण कंपनी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश के 75 प्रमुख शहरों में वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 7,09,793 आवासीय इकाइयाँ बिकीं, जो पिछले वित्त वर्ष की 7,19,029 इकाइयों से थोड़ी कम है। हालांकि, मूल्य के हिसाब से बिक्री 9,32,965 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो यह दर्शाता है कि प्रॉपर्टी की औसत कीमतें बढ़ी हैं। इसी अवधि में नए घरों की आपूर्ति 10 प्रतिशत बढ़कर 6,20,842 इकाई हो गई। आपूर्ति में वृद्धि के कारण बिना बिके मकानों (अनसोल्ड इन्वेंट्री) की संख्या में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह लगभग 12 लाख इकाई तक पहुंच गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि शीर्ष आठ शहरों में बिक्री थोड़ी घटकर 5,07,850 इकाई रही, जबकि दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में भी बिक्री में मामूली गिरावट आई।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 479 , निफ्टी 118 अंक गिरा

मुम्बई ।

घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी होने से आई है। आज सुबह बाजार खुलते ही तेजी दिखी पर समय बीतने के साथ ही बाजार का रुख बदलने लगा और उसमें गिरावट आने लगी। दिन भर के कारोबार के बाद दोनों बेंचमार्क इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए पर मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में तेजी रही। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 479 अंक टूटकर 76,009 के स्तर पर बंद हुआ जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी दिन के अंत में 118 अंक नीचे आकर 23,913 के स्तर पर बंद हुआ।

निफ्टी की कंपनियों में सबसे ज्यादा उछाल अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में आया।

इसके अलावा टाटा मोटर्स , टेक महिंद्रा के अलावा नेस्ले इंडिया के शेयरों में भी तेजी रही। दूसरी ओर अपोलो अस्पताल के अलावा विप्रो , भारती एयरटेल और ट्रेंट के शेयर गिरे। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी मेटल, निफ्टी एनर्जी के अलावा निफ्टी कमोडिटीज में तेजी रही जबकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज , निफ्टी सर्विसेज सेक्टर और रियल्टी शेयरों में गिरावट रही।

वहीं इससे पहले आज सुबह सेंसेक्स भी 141.36 अंक की गिरावट के साथ 76,347.60 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी मिडकैप में हल्की 0.14 फीसदी की तेजी रही, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 0.65 फीसदी की मजबूत बढ़त के रही। ड्यूरेबल, हेल्थकेयर और रियल्टी इंडेक्स दबाव में रहे, वहीं सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बाजार को कुछ सहारा दिया।

यह गिरावट अमेरिका द्वारा दक्षिणी ईरान में किए गए ताजा सैन्य हमलों के बाद बढ़ी वैश्विक अनिश्चितता के कारण आई है। वहीं गत दिवस बाजार तेजी के साथ बंद हुआ था।

श्रीलंका में केंद्रीय बैंक का बड़ा कदम, ब्याज दरों में एक फीसदी की बढ़ोतरी

तीन साल में पहली बार बढ़ी दरें, वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें बनी वजह

कोलंबो ।

श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीतिगत फैसले में अपनी प्रमुख नीतिगत ब्याज दर में एक प्रतिशत अंक (100 आधार अंक) की वृद्धि कर दी है। यह बीते तीन वर्षों में पहली बार है जब केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति को सख्त किया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य घरेलू मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच कमजोर पड़ रहे श्रीलंकाई रुपये को सहारा देना है। मौद्रिक नीति बोर्ड की बैठक के बाद लिए गए इस निर्णय से ओवरनाइट नीतिगत दर (ओपीआर) अब बढ़कर 8.75 प्रतिशत हो गई है। इसके साथ ही, मानक जमा सुविधा दर (एसडीएफआर) को 8.25 प्रतिशत और स्थायी उधारी सुविधा दर (एसएलएफआर) को 9.25 प्रतिशत कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दर में वृद्धि का यह निर्णय घरेलू और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। बैंक ने विशेष रूप से पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और इसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल सहित अन्य जिंसों की कीमतों में हो रही वृद्धि का हवाला दिया, जिसका सीधा असर वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि आने वाले समय में मुद्रास्फीति पांच प्रतिशत के उसके लक्ष्य से ऊपर बनी रह सकती है, हालांकि बाद में इसके स्थिर होने की संभावना है। इसके

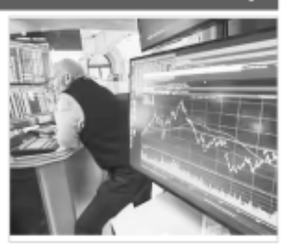

अतिरिक्त, श्रीलंकाई रुपये पर हाल के हफ्तों में दबाव देखा गया है, जो इस साल की शुरुआत से 22 मई तक 7.2 प्रतिशत कमजोर हो चुका था। हालांकि, बैंक का कहना है कि अब स्थिति में कुछ हद तक स्थिरता आई है।

प्रीमियर एनर्जीज में 2,291 करोड़ का संस्थागत निवेश

नई दिल्ली।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड में वैश्विक और घरेलू वित्तीय संस्थानों ने बड़ा दांव लगाया है। नोमुरा एसेट मैनेजमेंट और कैपिटल ग्रुप सहित कई संस्थागत निवेशकों ने कंपनी में 2,291 करोड़ रुपये में 5.3 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। यह सौदा खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से संपन्न हुआ। इस सौदे में कनाडा के पब्लिक सेक्टर पेंशन इन्वेस्टमेंट बोर्ड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे विदेशी निवेशक, और क्वांट म्यूचुअल फंड, बजाज फिनसर्व, बंधन म्यूचुअल फंड के साथ-साथ एचडीएफसी लाइफ व एसबीआई लाइफ जैसी प्रमुख घरेलू संस्थाएं शामिल रहीं। कंपनी के चार प्रवर्तकों ने औसतन 955 रुपये प्रति शेयर के भाव से कुल 2,39,85,197 शेयर बेचे, जिससे उनकी हिस्सेदारी 63.94 प्रतिशत से घटकर 58.65 प्रतिशत हो गई। यह निवेश ऐसे समय में हुआ है जब प्रीमियर एनर्जीज को हाल ही में 1,600 मेगावाट क्षमता के सौर सेल एवं मॉड्यूल की आपूर्ति के लिए 2,577 करोड़ रुपये के बड़े ऑर्डर मिले हैं।

भारत-कनाडा एफटीए 2030 के अंत तक 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य

पीयूष गोयल और मनिंदर सिद्धू ने जताई प्रतिबद्धता; तीसरे दौर की वार्ता ओटावा में जारी

नई दिल्ली।

भारत और कनाडा इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी कनाडा यात्रा के दौरान यह घोषणा की, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। ओटावा में कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस साल के अंत तक इस समझौते को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। गोयल ने कहा कि हमारा उद्देश्य मौजूदा 17 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 2030 तक 50 अरब डॉलर करना है। अपनी यात्रा के दौरान गोयल ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से भी मुलाकात की, जिन्होंने एफटीए को कनाडाई कामगारों और कारोबार के लिए गेम चेंजर बताया। कार्नी ने ऊर्जा, कृषि-खाद्य, प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं भी गिनाईं। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता 25 से 29 मई तक ओटावा में जारी है। भारत की ओर से संयुक्त सचिव बृजमोहन मिश्रा और कनाडा की ओर से ब्रूस क्रिस्टी मुख्य वार्ताकार हैं। द्विपक्षीय व्यापार में दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दालें और कच्चा पेट्रोलियम प्रमुख मदें हैं, जबकि कनाडा में 4.25 लाख से अधिक भारतीय छात्र और एक बड़ा भारतीय समुदाय भी रहता है।

यूपीआई पेमेंट में बदलाव, अब दुकानों पर दिखेगा सिर्फ एक स्मार्ट साउंडबॉक्स!

एनपीसीआई ला रहा वन साउंडबॉक्स रूल, सभी ऐप्स के लिए एक ही डिवाइस देगा पेमेंट की जानकारी

नई दिल्ली ।

भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में एक महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी है। अब दुकानों पर गूगल प्ले, फोनपे और पेटीएम जैसे अलग-अलग यूपीआई ऐप्स के लिए कई साउंडबॉक्स रखने की झंझट खत्म होने वाली है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) एक नया नियम लाने जा रहा है, जिसका लक्ष्य पेमेंट अनुभव को और भी सुव्यवस्थित करना है। एनपीसीआई अब वन साउंडबाक्स रूल लागू करने की दिशा में काम कर रहा है, जिसके तहत इंटरोपेरेबल साउंडबाक्स तकनीक विकसित की जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि दुकानदारों को अब कई कंपनियों के अलग-अलग साउंडबॉक्स रखने की जरूरत नहीं होगी।

भविष्य में सिर्फ एक ही स्मार्ट साउंडबॉक्स होगा जो किसी भी यूपीआई ऐप से आने वाले पेमेंट की जानकारी और पुष्टि आवाज के माध्यम से देगा। यह सुविधा उसी तरह काम करेगी जैसे आज एक क्यूआर कोड सभी यूपीआई ऐप्स के साथ संगत होता है। यह पहल विशेष रूप से छोटे दुकानदारों के लिए एक बड़ी राहत होगी। उन्हें अब काउंटर पर कई डिवाइस रखने, उनका मासिक किराया या खर्च चुकाने और जगह घेरने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इससे उनके काउंटर साफ-सुथरे और व्यवस्थित दिखेंगे, संचालन लागत में कमी आएगी और डिजिटल पेमेंट को अपनाना और भी आसान हो जाएगा। इस बदलाव से डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम और परिपक्व होगा।

पुराने गहने एक्सचेंज करने पर लग सकता है कैपिटल गेन टैक्स!

टैक्स विशेषज्ञः यह सिर्फ डिजाइन बदलना नहीं, संपत्ति का हस्तांतरण है

नई दिल्ली ।

भारत में अक्सर लोग पुराने गहनों को एक्सचेंज कर नए डिजाइन बनवाते हैं, लेकिन यह आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्रक्रिया केवल डिजाइन बदलने तक सीमित नहीं, बल्कि इनकम टैक्स नियमों के तहत एसेट ट्रांसफर यानी संपत्ति का हस्तांतरण माना जा सकता है, जिस पर कैपिटल गेन टैक्स भी लागू हो सकता है। आयकर कानून के तहत पुराने गहनों के बदले नए गहने लेना भी ट्रांसफर माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने सालों पहले कम कीमत पर सोना खरीदा था और अब एक्सचेंज के दौरान उसकी कीमत काफी बढ़ गई है, तो बढ़ी हुई वैल्यू पर कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ सकता है। भले ही उपभोक्ता को सीधे नकदी न मिली हो, टैक्स विभाग इसे संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में देखेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, पुश्तैनी और पुराने गहनों के मामले में यह दिक्कत ज्यादा होती है, क्योंकि अक्सर इनकी खरीद के दस्तावेज या असली कीमत का रिकॉर्ड नहीं मिलता, जिससे टैक्स की गणना जटिल हो जाती है। विरासत या वसीयत में मिले गहनों पर भी यही नियम लागू हैं, जहां पुराने मालिक की खरीद कीमत आधार बनती है। 1 अप्रैल 2001 की कीमत कैपिटल गेन गणना में महत्वपूर्ण है।

आजकल ज्वेलर्स भले ही आसानी से एक्सचेंज की सुविधा दे रहे हों, पर बिना सही रिकॉर्ड और मूल्यांकन के भविष्य में दिक्कत हो सकती है। टैक्स विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गहनों के एक्सचेंज से पहले खरीद तारीख, अनुमानित कीमत और सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच जरूर कर लें, ताकि भविष्य में किसी टैक्स नोटिस या अतिरिक्त बोझ से बचा जा सके।

अदाणी ग्रीन ने 3.3 गीगावाट घंटा बैटरी स्टोरेज क्षमता हासिल की

खावड़ा परियोजना भारत के ऊर्जा भविष्य में निभा रही बड़ी भूमिका

नई दिल्ली।

अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने गुजरात के खावड़ा में अपनी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की परिचालन क्षमता को बढ़ाकर 3.37 गीगावाट घंटा (जीडब्ल्यूएच) कर दिया है। मार्च 2026 में 1.37 गीगावाट घंटा की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने के बाद, यह संयंत्र अब चीन के बाहर एक ही स्थान पर स्थापित दुनिया की सबसे बड़ी और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से लागू की गई बैटरी भंडारण परियोजना बन गया है। खावड़ा में एजीईएल 30 गीगावाट का एक विशाल नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित कर रहा है, जिसमें से 9.9 गीगावाट पहले ही चालू हो चुका है। यह 3.37 गीगावाट की बीईएसएस क्षमता लगभग 10 लाख घरों को एक दिन तक स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने या 1.2 करोड़ से अधिक एलईडी बल्बों को 10 घंटे तक लगातार ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है। कंपनी की योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 10 गीगावाट घंटा से अधिक बैटरी भंडारण क्षमता जोड़ने और अगले पांच वर्षों में इसे 50 गीगावाट तक पहुंचाने की है। एजीईएल के कार्यकारी निदेशक सागर अदाणी ने इस उपलब्धि पर जोर देते हुए कहा, ‘बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव के अगले चरण में अहम भूमिका निभाएगा। विश्वसनीय और 24 घंटे स्वच्छ बिजली आपूर्ति के लिए भंडारण अवसंरचना जरूरी है।’ एजीईएल का कुल परिचालन नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो अब 19.7 गीगावाट है।

राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान, JMM को 'ऑपरेशन लोटस' का डर

बीजेपी की उम्मीदवारी पर उठे सवाल

चुनाव आयोग से विशेष निगरानी की मांग

रांची ।

झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बीजेपी पर धनबल, अनैतिक दबाव और विधायकों की खरीद-फरोख्त की आशंका जताई है। पार्टी ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद बीजेपी का चुनाव मैदान में उतरना कई सवाल खड़े करता है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे पत्र में कहा है कि राज्य विधानसभा में गठबंधन के पास कुल 56 विधायकों का समर्थन है। इसमें झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और भाकपा (माले) के 2 विधायक शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार की जीत के लिए कम से कम 28 प्रथम वरीयता मतों की जरूरत होती है। ऐसे में गठबंधन का दावा है कि दोनों सीटों पर उसकी जीत तय है।

रणनीति पर सवाल

झामुमो ने सवाल उठाया है कि जब बीजेपी के पास केवल 21 विधायक हैं, तब भी वह चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार क्यों उतार रही है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी धनबल और दबाव की राजनीति के जरिए कुछ विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकती है। राजनीतिक गलियारों में इसे ÷ऑपरेशन लोटस÷ की आशंका के तौर पर देखा जा रहा है। झामुमो ने कहा कि बीजेपी चुनावी गणित के बजाय राजनीतिक तोड़फोड़ की रणनीति पर काम कर सकती है।

आयोग से निगरानी की मांग

झामुमो ने चुनाव आयोग से राज्यसभा चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में कराने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर विशेष निगरानी रखी जाए और केंद्रीय एजेंसियों को भी सतर्क किया जाए। पत्र में सीबीआई, ईडी, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग और झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो को सक्रिय रखने की मांग की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त या दबाव की राजनीति को रोका जा सके।

दो सीटों पर होगा चुनाव

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव होना है। इनमें एक सीट शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी, जबकि दूसरी सीट बीजेपी नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल समाप्त होने के कारण रिक्त हो रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले झामुमो के इस पत्र ने झारखंड की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है।

सीबीएसई ने मानी आंसर-शीट मूल्यांकन में हुई गलती, छात्रों को भेजी सही कॉपियां

12वीं कक्षा के परिणाम भी संशोधित और नए अंकों के आधार पर अपडेट होंगे

नई दिल्ली।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं कक्षा के नतीजों को लेकर छात्रों द्वारा उठाई गई शिकायतों पर बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने फिजिक्स और केमिस्ट्री विषयों की आंसर शीट के मूल्यांकन में हुई गलतियों को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है। शिकायत दर्ज कराने वाले प्रभावित छात्रों को बोर्ड ने अब सही आंसर शीट भेज दी हैं। इसके साथ ही सीबीएसई ने ईमेल के जरिए छात्रों को भरोसा दिलाया है कि 12वीं कक्षा के उनके परीक्षा परिणाम भी संशोधित और नए अंकों के आधार पर अपडेट कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने शिकायत करने वाले छात्रों को एक ईमेल के जरिए बताया कि 12वीं क्लास के छात्रों के नतीजे भी नए अंकों के आधार पर अपडेट किए जाएंगे। एक छात्र ने जिसने पहले अपनी 12वीं क्लास की फिजिक्स आंसर शीट में गलतियों का मुद्दा उठाया था। एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमें सीबीएसई से अपनी सही आंसर शीट मिल गई है। सीबीएसई के अधिकारियों ने शाम को हमसे संपर्क किया और आंसर शीट भेज दी।

हमारे दावे सही निकले और सच में आंसर शीट बदल गई थी। एक और छात्रा जिसने अपनी 12वीं क्लास की केमिस्ट्री आंसर शीट में गड़बड़ी की शिकायत की थी, उसने एक्स पर पोस्ट किया की सीबीएसई ने हमारे ईमेल का जवाब दिया और पुष्टि की कि केमिस्ट्री आंसर शीट के बारे में हमारी चिंता सही थी। अब हम सीबीएसई की तरफ से अगले कदमों का इंतज़ार कर रहे हैं।

केरल के सीएम वीडी सतीशन ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सीबीएसई 12वीं के नतीजों और 2025-26 के लिए पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर मिली व्यापक शिकायतों के बारे में एक ईमेल भेजा। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने पारदर्शिता, निष्पक्षता और छात्रों की शिकायतों के समय पर समाधान को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। सीबीएसई 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए विंडो 26 मई को खोल दी है। छात्र 29 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर अंकों के सत्यापन और वास्तविक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी के लिए आवेदन किया है, वे ही पाई गई गलतियों के सत्यापन और/या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

आवेदक को संबंधित विषय की मार्किंग स्कीम देखनी होगी, जो प्रश्न पत्र के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

कच्चा तेल सस्ता, फिर भी ईंधन महंगा क्यों? खड़गे ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना

नई दिल्ली।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधनों की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र पर तीखा हमला बोल दिया है। यह हमला तब किया हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 12 साल पूरे होने पर भाजपा इस बात को उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पोस्ट कर तंज कसा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फारसी क्या! उन्होंने प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के आंकड़ों का हवाला देकर बताया कि 26 मई 2014 को, जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तब भारतीय बास्केट में कच्चे तेल की कीमत 108.05 डॉलर प्रति बैरल थी और डॉलर-रुपया विनिमय दर 58.59 रुपये थी। उस समय पेट्रोल 71.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 56.71 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि वर्तमान में कच्चे तेल की कीमत 99 डॉलर प्रति बैरल से भी कम है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़कर क्रमशः102.12 रुपये और 95.20 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं। उन्होंने दावा किया कि कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल करीब 42.8 प्रतिशत और डीजल करीब 67.9 प्रतिशत अधिक महंगा हो गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि हर अर्थशास्त्री इस बात से सहमत है कि पेट्रोल-डीजल की महंगाई का सीधा असर परिवहन से लेकर खाद्य वस्तुओं तक हर क्षेत्र पर पड़ता है, इससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर मुनाफाखोरी का आरोप लगाकर प्रश्न किया कि जब

वैश्विक स्तर पर कच्चा तेल सस्ता हुआ है, तब जनता को राहत क्यों नहीं दी जा रही है और ईंधन की कीमतें कम क्यों नहीं की जा रही हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में गैस वितरण कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पिछले दो हफ्तों से भी कम समय में यह चौथी बढ़ोतरी है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है, जिसके बाद अब यह 81.09 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

ट्रेलर में घुसी इनोवा, कैंची धाम जा रहे 4 श्रद्धालुओं की मौत, 3 गंभीर

बाराबंकी में सुल्तानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा

बाराबंकी।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां सुल्तानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार इनोवा कार आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। इस भीषण टक्कर में कार सवार चार श्रद्धालुओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के भिखरा गांव के पास देर रात करीब दो बजे हुआ। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग भीतर ही बुरी तरह फंस गए। आधी रात को हुए इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, जिसे सुनकर दौड़े राहगीरों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी। जानकारी के अनुसार, कार में सवार सभी सात लोग उत्तराखंड स्थित प्रसिद्ध बाबा नीम करौली के कैंची धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार हैदरगढ़ क्षेत्र में पहुंची, सुल्तानपुर से लखनऊ की ओर जा रहे एक ट्रेलर से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद कार को काटकर घायलों और शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ पहुंचाया, जहां से उनकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। हादसे की खबर जैसे ही मृतकों के परिजनों को मिली, उनके घरों में कोहराम मच गया। इस सड़क हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की पहचान राहुल कुमार (पुत्र संजय कुमार, निवासी मुगलसराय, जनपद चंदौली), राहुल सिंह (पुत्र अजय प्रताप, निवासी गैबीपुर, जनपद गाजीपुर), सत्यम सिंह (पुत्र स्वर्गीय तेज प्रताप सिंह, निवासी रामपुर रसड़ा, जनपद बलिया) और सूरज मिश्रा (निवासी निकसपुर, थाना सुल्तानपुर) के रूप में हुई है।

कॉकरोच जनता पार्टी के नाम साइबर ठगी का पहला मामला दर्ज, साइबर ठगोरे ने लिंक भेज उड़ाए 96 हजार

इन्दौर ।

आनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले ये शातिर साइबर ठगोरे नित नये पैंतरे अपनाते रहते हैं, जिनमें सर्वाधिक वें होते हैं जो आम जन के रोजमर्रा जीवन-शैली से संबंधित अथवा समयानुकूल या बहुचर्चित होते हैं, जिससे आम जन सहज ही उनकी ओर आकर्षित हो उनके जाल में फंसकर ठगी का शिकार हो जाता है। ऐसे ही अब इन शातिर साइबर ठगोरों ने इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी नाम पर ठगी की वारदात करना शुरू कर दिया है और इन्दौर में इस तरह की ठगी का पहला मामला दर्ज भी हो चुका है। मामले में शातिर साइबर ठगोरे ने कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करने और पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर एक पीड़ित को फिशिंग लिंक भेजी जिसे क्लिक करते ही उसका मोबाइल हैक हो गया और उसके खाते से 96 हजार रुपए उड़ा ली गई। पीड़ित के मोबाइल पर यह फिशिंग लिंक उसके दोस्त के नंबर सात भेजी गई थी जिसे भी साइबर ठगोरे ने हैक कर लिया था।

मामला शहर के रामबाग क्षेत्र का है और पीड़ित एक डॉक्टर दंपती के यहां ड्राइवर है। उसने कल जोन-1 डीसीपी कार्यालय पर शिकायत दर्ज कराते बताया कि शुक्रवार रात गांव में रहने वाले उसके एक मित्र के व्हाट्सऐप नंबर से मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था कि यदि आपको कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करना है तो लिंक पर क्लिक करें। साथ ही पीएम आवास योजना के तहत मकान और लोन दिलाने का भी कहा गया। उसने भरोसे में आकर लिंक क्लिक कर दी। इसके बाद उसका मोबाइल अचानक स्लो हो हैंग होने लगा। जिसके चलते उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और करीब दो घंटे बाद से जब मोबाइल चालू किया तो बैंक खाते से 96 हजार रुपए अधिक राशि दूसरे खाते में ट्रांसफर हो चुकी थी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि जिस मित्र के नंबर से ड्राइवर को लिंक मैसेज आया था ठगोरों ने उस मित्र का मोबाइल भी हैक किया था। इसके बाद उसकी

कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों को उसी नंबर से फिशिंग लिंक भेजी गई। मित्र का नंबर देखकर पीड़ित ने लिंक खोली और साइबर ठगी का शिकार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में साइबर सेल की मदद से गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

ओडिशा में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन टैंक में उतरे 6 मजदूरों की गई जान

एक की जान बचाने की कोशिश में गई छह जिंदगियां

जहरीली गैस की चपेट में आने से हुआ हादसा

भुवनेश्वर ।

ओडिशा के कालाहांडी जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक के अंदर जहरीली गैस के कारण दम घुटने से यह हादसा हुआ। घटना मदनपुर-रामपुर थाना क्षेत्र के गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। प्रारंभिक जांच के मुताबिक, सभी मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए थे। वे सेप्टिक टैंक के भीतर लगे सेंट्रिंग सामग्री को निकालने के लिए अंदर उतरे थे।

इसी दौरान टैंक में मौजूद जहरीली गैस की चपेट में आने से एक के बाद एक मजदूर बेहोश होकर गिर पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब एक व्यक्ति टैंक के भीतर अचेत हुआ तो उसे बचाने के प्रयास में अन्य लोग भी अंदर गए, लेकिन वे भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। देखते ही देखते छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। इसके बाद बचाव अभियान चलाकर सभी शवों को टैंक से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं।

बरेली एसएसपी का कड़ा एक्शनः रील, घूसखोरी और शिकायत दबाने पर तीन दारोगा नपे

बरेली ।

उत्तरप्रदेश के बरेली जिले में एसएसपी ने अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने अवैध वसूली और महिला संबंधी गंभीर शिकायत दबाने के मामलों में तीन दारोगाओं पर एक्शन लिया है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पहला मामला दारोगा शुभम सोम से जुड़ा है, जो एसआई शुभ ठाकुर नाम की इंस्टाग्राम आईडी से वर्दी का रौब दिखाकर सोशल मीडिया नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। जांच में आरोप सही साबित होने पर एसएसपी ने उन्हें तत्काल लाइन हाजिर किया है। दूसरा मामल दारोगा शुभम चौधरी का है। उन पर राहुल शंखधार नामक युवक को अवैध हिरासत में रखकर मारपीट करने और पचास हजार रुपये वसूलने का गंभीर आरोप है। शुरुआती जांच में आरोप पुष्ट होने पर दारोगा को निलंबित कर गहन जांच शुरू की है। तीसरा मामला हाफिजगंज क्षेत्र की महिला की छेड़खानी और मोबाइल तोड़ने की शिकायत को दारोगा चंद्रपाल सिंह द्वारा दबाने का है, जिसमें एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। लापरवाही सामने आते ही एसएसपी ने उन्हें भी निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे को साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वर्दी पहनने के बाद रील बनाना या जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना बर्दाश्त नहीं होगा। जनता के साथ किसी भी स्तर पर लापरवाही या गलत व्यवहार करने वालों पर ऐसी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गाजियाबाद- जनगणना अधिकारी को घर लाने पर पड़ोसी को मारी गोली

गाजियाबाद ।

गाजियाबाद में जनगणना अधिकारियों को पड़ोसी के घर ले जाना प्रॉपर्टी डीलर को महंगा पड़ गया, जब एक नाराज पड़ोसी ने उस पर गोली चला दी। यह घटना आदर्श नगर कॉलोनी में हुई, जहां प्रॉपर्टी डीलर वीरेंद्र त्यागी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि आरोपी रामपाल चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, जनगणना अधिकारी त्यागी के घर पहुंचे और परिवार की जानकारी दर्ज की। इसके बाद, उन्होंने त्यागी से कॉलोनी के अन्य घरों का पता बताने में मदद मांगी। त्यागी अधिकारियों को लेकर अपने पड़ोसी रामपाल चौधरी के घर पहुंचे, जिससे रामपाल आग बबूला हो गए। उन्होंने वीरेंद्र त्यागी के साथ गाली-गलौज करते हुए डंडा लेकर उन्हें और अधिकारियों को दौड़ाया। जनगणना अधिकारियों ने तत्काल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही रामपाल फरार हो चुका था। दोपहर करीब 12 बजे, रामपाल चौधरी दोबारा वीरेंद्र त्यागी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही वीरेंद्र त्यागी ने दरवाजा खोला, रामपाल ने देसी पिस्तौल से गोली चला दी, जो वीरेंद्र के पेट में जा लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य और पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। घायल वीरेंद्र त्यागी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। मुरादनगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ अंकित कुमार ने बताया कि आरोपी रामपाल चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि देशभर में नई जनगणना प्रक्रिया की तैयारियां चल रही हैं, जिसके तहत अधिकारी घर-घर जाकर परिवारों का ब्योरा इकट्ठा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जनगणना अधिकारी गाजियाबाद पहुंचे थे, और इसी प्रक्रिया के दौरान यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई।

बिहार में एमएलसी चुनाव का ऐलान, 18 जून को मतदान, उसी दिन परिणाम

9 सीटों पर होगा चुनाव, इनमें नीतीश और चौधरी की खाली की गई सीटें भी शामिल

पटना।

चुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषित की, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी द्वारा पिछले साल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद खाली की गई सीट भी शामिल है। चुनाव आयोग ने पूर्व बिहार सीएम नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद खाली की गई विधान परिषद सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की। चुनाव आयोग के जारी कार्यक्रम के मुताबिक सभी 9 सीटों के लिए मतदान, उपचुनाव समेत, 18 जून को होगा और मतगणना उसी शाम की जाएगी। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया 20 जून तक समाप्त होने की उम्मीद है। चुनाव अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी। उम्मीदवार 11 जून तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बिहार विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है, उनमें कुमुद वर्मा, गुलाम गौस, मोहम्मद फारूक, भीष्म साहनी, संजय प्रकाश, समीर कुमार सिंह और सुनील कुमार सिंह शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर भगवानसिंह कुशवाहा और सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अपनी विधानसभा सीटें खाली कर दीं। राज्य के सबसे लंबे समय तक सीएम रहे नीतीश कुमार के मार्च में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उपचुनाव जरूरी हो गया है।

केबल-कारों में फंसे 320 लोगों को बचाने वाली टीम के साथ खड़े होना गर्व की बात

डीजीपी ने कहा- हरेक को बहादुरी और समर्पण के लिए किया जाएगा सम्मानित

श्रीनगर।

जम्मू-कश्मीर के डीजीपी ने मंगलवार को कहा कि गुलमर्ग में फंसे केबल कार के केबिनों से 320 लोगों को सुरक्षित निकालना बचाव टीमों के साथ खड़ा होना उनके लिए गर्व का क्षण था। डीजीपी ने जम्मू-कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और स्थानीय बचाव दल की टीमों से कहा कि सच कहूं तो, मुझे विश्वास नहीं था कि हम आधी रात से पहले यह काम पूरा कर पाएंगे। डीजीपी ने कहा कि गुलमर्ग पुलिस स्टेशन की टीमें सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचीं लेकिन तुरंत ही सेना, जम्मू-कश्मीर सशस्त्र पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय बचाव दल भी उनके साथ जुड़ गए। सभी ने अत्यंत समन्वित और पेशेवर तरीके से काम करते हुए बचाव अभियान को पूरा किया और 320 फंसे हुए लोगों को नीचे उतारा। उन्होंने कहा कि जमीनी बचाव कार्य उतना चुनौतीपूर्ण और कठिन नहीं था, जितना कि खराब मौसम में दुर्गम पहाड़ी इलाकों में कार के केबिन में फंसे लोगों को बचाना। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हमें हमेशा सबसे कठिन चुनौतियां दी गई हैं और हमने हमेशा उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया है।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीजीपी ने छह घंटे तक चले इस असाधारण अभियान के दौरान गुलमर्ग पुलिस स्टेशन, एसओजी, जम्मू-कश्मीर सशस्त्र पुलिस, पर्वतीय बचाव दल (एमआरटी), एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के कर्मियों के असाधारण प्रयासों के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि आप थके हुए, भूखे-प्यासे हो सकते हैं लेकिन मुझे यकीन है कि आप सभी खुश हैं क्योंकि आज आपको एक उद्देश्य दिया गया था और आपने उसमें सफलता हासिल की। डीजीपी ने घोषणा की कि बचाव अभियान में लगे प्रत्येक व्यक्ति को उनकी बहादुरी और समर्पण के सम्मान में डीजी प्रशस्ति पदक से सम्मानित किया जाएगा।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। RNI No. RAJHIN/2001/05699 मो. नं. 9928078717